छोटे किसानों को ऋण

2507. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि इन्स्टीच्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि छोटे किसानों को पर्याप्त ऋण/साख सुविधाएं मिलनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) और (ख) छोटे और सीमांत किसानों के लिये पर्याप्त ऋण की व्यवस्था के लिये विकास अध्ययन संस्थान से कोई सिफारिश नही मिली है।

लेकिन, ऋणों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने संचालन क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के लिये धन की व्यवस्था करने में कार्यनिष्पादन का एक न्यूनतम स्तर हासिल करना (कुल वितरित ऋण के 10 से 151 के बीच) निर्धारित किया है।

Marketing Reforms in the Farm Sector

2508. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether in the light of the observations made in the Economic Survey for 1998-99 Government have taken fresh initiatives to formulate, finalise and implement marketing reforms in the farm sector;

(b) if so, furnish details regarding the present status of marketing systems of agro-products in various States, State-wise and nature of reforms proposed to be implemented; and

(c) how soon the reforms in marketing of farm sector are likely to be ready for implementation for Maharashtra in particular?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Government have formulated various schemes, namely, Development of Rural Market, Market Extension, Improvement of Services in wholesale Markets, Setting up of Apni Mandi and creation of additional Storage and Cold Storage capacity in order to minimise the gap between the producer price and the consumer price due to a large number of intermediaries operating in unregulated and unsupervised vegetable and fruit market. Action has also been initiated to review, and abolish wherever feasible, all control on the movement of agricultural products and on the processing of agricultural products, in order to ensure a higher return to the grower.

Besides, a draft Model State Act for Agricultural Produce Marketing Regulation was circulated to all State Governments/Union Territories for enacting appropriate legislations. Most of the State Governments/ Union Territories have enacted their legislations on the basis of this Model State Act for agricultural produce markets.

The Marketing system of agro-products varie from State to State. All States except manipur, Kerala, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Dadra and Nagar Haveli have enacted the legislation.

(c) Agricultural marketing being a State subject, the time frame for reforms in marketing of farm sector is to be decided and implemented by the respective State Governmetns under the provisions of their State Agricultural Produce marketing Regulation Acts. In the State of Maharashtra, the action is to be taken under the provisions of the Maharashtra Agricultural Produce marketing (Regulation) Act, 1963 (Act No. XX of 1964).

Agricultural Extension Services

2509. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to revamp agricultural extension services in the country;

(b) if so, what are details thereof; and

(c) in what way it will be advantageous to the farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) Extension programmes are being restructured with the following objectives:

- Making extension services demand driven;
- Moving towards integrated extension delivery;
- Taking up capacity building programmes for extension institutions, personnel and farmers;
- Addressing gender issues in agriculture;
- Piloting new institutional arrangements for transfer of technology and
- Promoting use of information technology.

(c) Restructured extension system will be able to better serve the technological needs of the farmers.

Loss of Lives due to Cyclone in Gujarat

2510. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of lives lost as per latest assessment in the cyclones that hit the Kandla and other Gujarat Coasts in August last year;

(b) the number of applications for compensation and relief of victims' families; and

(c) the amount so far released from Prime Minister's Relief Fund for these victims and whether these are actually paid to the victims families?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The Government of Gujarat has reported that, as per the latest assessment, 1751 persons reportedly died due to the cycloen of June, 1998. The State Government has provided ex-gratia relief amounting to Rs. 1005.85 lakh to the families/ heirs of the victims in 1172 cases. The State Government had received Rs. 651.50 lakh from the Prime Minister's Relief Fund for these victims and Rs. 538.00 lakh has been actually paid to the families of the victims.

हरित क्रांति में क्षत्रीय असंतुलन

2511. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **:**

(क) क्या यह सच है कि हरित क्रांति से केवल सिंचित क्षेत्र को ही फायदा हुआ है और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कार्रवाई कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) हरित क्रांति से मुख्यतया सिंचित क्षेत्रों को अंसिंचित या वर्षा सिंचित क्षेत्रों की तुलन में लाभ हुआ है जहां बुनियादी ढ़ांचे की बेहतर सुविधाएं सुलभ है ।

(ख) सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिये असिंचित/वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास करने को उच्चतम प्राथमिकता दी है । "वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना" प्रमुख कार्यक्रम है जो देश के सभी प्रखंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है । फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये फसल विकास योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है । नौंवी योजना के दौरान, कृषि विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों की कृषि-जलवायुयीय स्थितियों के आधार पर क्षेत्रीय तौर पर भिन्न-भिन्न कार्यनीतियां अपनाना प्रतिपादित किया गया है ।

उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग

2512. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि "हरित क्रांति" के दौरान उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरा –शक्ति प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रक्रिया को दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम (एन.पी.के.) के रूप में उर्वरक की औसत खपत प्रति हैक्टयर 87.46 कि0 ग्रा0 होने का अनुमान है । अन्य देशों के साथ की गई तुलना से पता चलता है कि पाकिस्तान (113 कि0ग्रा0), बंगलादेश(135 कि0ग्रा0), नीदरलैण्ड (543 कि0ग्रा0) और चीन (371 कि0ग्रा0) जैसे देशों में उर्वरक की खपत कहीं अधिक है ।

भारत में उर्वरक की खपत की लाभकारी प्रतिक्रिया है और अधिक उपज मिलती है, कृषि वैज्ञानिक उर्वरक पोषकों की अधिक खुराक की सिफारिश करते है । इसे दृष्टिगत रखते हुए, यह नही कहा जा सकता कि भारत में उर्वरकों का अत्याधिक उपयोग हो रहा है ।

तथापि, सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है जिसमें मुद्रा की उर्वरता